

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

विषय:- जनपद-देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड स्थित इन्डोर स्टेडियम के निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1463/बजट/संबंधित निर्माण पत्रा/2017-18/देहरादून, दिनांक 24 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड स्थित इन्डोर स्टेडियम के निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में टी०८०सी० द्वारा संस्तुत ₹ 1439.06 लाख (सिविल निर्माण कार्यों हैतु ₹ 810.86 लाख तथा अधिग्राहित नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हैतु ₹ 628.20 लाख) की धनराशि भारत सरकार के पत्र संख्या:-46-1/MYAS/Khelo India/2016/1692, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा कार्य हैतु ₹ 800.00 लाख (वस्तुत लागत ₹ 1439.06 लाख) पर सहमति प्रदान करते हुये प्रथम किशत के रूप में ₹ 250.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार भारत सरकार से कुल प्राप्त धनराशि ₹ 800.00 लाख के सापेक्ष ₹ 250.00 लाख की धनराशि एवं राज्य सरकार के द्वारा कार्य हैतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-526 /VI/2016-22(9)/2012-T.C-IST, दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त इस प्रकार भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के रूप में ₹ 250.00 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्य हैतु ₹ 500.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 750.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत कार्य हैतु भारत सरकार से अवशेष धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में कार्य में गति बनाये रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा देय अवशेष/अन्तिम धनराशि ₹ 139.06 लाख (₹ एक करोड़ उन्तालीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि संगत मानक मद से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०य०० अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।



3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
8. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
11. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-11-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-26-38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष के नामे डाला जायेगा।
12. यह स्वीकृत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :- अलाटमैट आई०डी० संख्या- ८१८०२११०३५७, दिनांक २७ फरवरी, 2018

भवदीय,

(अतर सिंह)

संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 95 /VI/2018-22(9) / 2012-T.C-1ST. तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. प्रमुख निजी सचिव, सचिव, खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. जिला कीडाधिकारी, देहरादून।
9. महाप्रबन्धक / परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।